



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]
No. 436]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, अक्टूबर 20, 2005/आश्विन 28, 1927
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 20, 2005/ASVINA 28, 1927

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अक्टूबर, 2005

सा.का.नि. 638(अ).—केन्द्रीय सरकार, विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 52 की उपधारा (2) के खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम समपहत संपत्ति की कीमत का अवधारण नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाएँ—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
(क) “अधिनियम” से विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) अभिप्रेत है;
(ख) “कीमत” से राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा नियम 4 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित समपहत संपत्ति की कीमत अभिप्रेत है;
(ग) “प्राधिकृत अधिकारी” से समपहत संपत्ति की कीमत का निर्धारण करने के लिए नियम 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी अभिप्रेत है;
(घ) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. प्राधिकृत अधिकारी की नियुक्ति—जहां कोई ऐसा व्यक्ति, जिसके विरुद्ध समपहरण का आदेश किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यक्ति कहा गया है) दोषमुक्त हो जाता है वहां सम्पत्ति उसे या उसके विधिक नामनिर्देशिनी को वापस की जाएगी और यदि किसी कारण से समपहत संपत्ति का वापस किया जाना संभव नहीं है तो राज्य सरकार उस सरकार में उप सचिव पंक्ति से अन्यून के किसी अधिकारी को नियुक्त करेगी जो समपहत संपत्ति के बदले में व्यक्ति को प्रतिकर प्रदान करने की दृष्टि से समपहत संपत्ति की कीमत का मूल्यांकन करने और कीमत नियत करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के नाम से जाना जाएगा।

4. समपहत संपत्ति की कीमत निर्धारित करते समय ध्यान में रखे जाने वाले कारक—

प्राधिकृत अधिकारी समपहत संपत्ति की कीमत नियत करते समय निम्नलिखित पर विचार करेगा :—

- (i) समपहत संपत्ति का बाजार मूल्य;

- (ii) ऐसी अन्य संपत्ति का मूल्य जो समपहृत संपत्ति के तुल्य हो;
- (iii) तात्त्विक लागत या संपरिवर्तन लागत; और
- (iv) ऐसे अन्य कारक जिन्हें वह कीमत का अवधारण करने में आवश्यक समझे।
5. अभ्यावेदन पर विचार—(1) प्राधिकृत अधिकारी, किसी व्यक्ति या उसके विधिक नामनिर्देशिती द्वारा किए गए किसी अभ्यावेदन को, यदि कोई हो, समपहृत की गई संपत्ति के संबंध में कीमत को अंतिम अवधारण करने से पूर्व ध्यान में रखेगा।
- (2) प्राधिकृत अधिकारी, तत्पश्चात् समपहृत संपत्ति की कीमत नियत करेगा और उसे लिखित में व्यक्ति या उसके विधिक नामनिर्देशिती को संसूचित करेगा।
6. केन्द्रीय सरकार को संपत्ति बेचे जाने के आदेश का जारी होना—राज्य सरकार, इस आशय का एक आदेश करेगी कि नियम 5 के अधीन नियत कीमत पर समपहृत संपत्ति केन्द्रीय सरकार को बेची गई है और उक्त आदेश की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के संबद्ध मंत्रालय या विभाग को स्पष्ट रूप से खजाने और उस लेखा-शीर्ष को उपदर्शित करते हुए जिसके अंतर्गत इस प्रकार अवधारित रकम जमा की जानी है, भेजेगी।
7. केन्द्रीय सरकार द्वारा रकम का जमा किया जाना—(1) केन्द्रीय सरकार नियम 6 के अधीन आदेश के प्राप्त होने पर व्यक्ति या उसके विधिक नामनिर्देशिती को सूचना के अधीन समपहृत संपत्ति के लिए नियत कीमत को ऐसे खजाने में या लेखा शीर्ष के अधीन जमा करेगी जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

- (2) कीमत और उस पर ब्याज सहित रकम का व्यक्ति या उसके विधिक नामनिर्देशिती को संदाय किया जाएगा।

[फा. सं. I-17014/52/2005-आईएस-VII]

एल. सी. गोयल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th October, 2005

G.S.R. 638(E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of Sub-section (2) of Section 52 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Determination of the Price of the Forfeited Property Rules, 2005.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires,—

- “Act” means the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967);
- “Price” means the price of the forfeited property determined by the officer authorized by the State Government in accordance with the provisions contained in rule 4;
- “Authorised Officer” means the officer appointed by the State Government under rule 3 to assess the price of the forfeited property;
- words and expressions used here but not defined but defined in the Act, shall have the same meanings as are assigned to them in the Act.

3. **Appointment of Authorised Officer.**—Where the person against whom an order of forfeiture has been made (hereinafter referred to as the person), is acquitted, the property shall be returned to him or his legal nominee and if it is not possible for any reason to return the forfeited property, the State Government shall appoint an officer not below the rank of Deputy Secretary to that Government, to be known as Authorised Officer, to evaluate and fix the price of the forfeited property with a view to compensating the person in lieu of the forfeited property.

4. **Factors to be taken into account while fixing price of the forfeited property.**—The Authorised Officer shall, while fixing the price of the forfeited property, take into consideration—

- the market value of the forfeited property;
- the value of such other property which is comparable to the forfeited property;

- (iii) the material cost or conversion cost; and
- (iv) such other factors which he may consider necessary in the determination of the price.

5. **Consideration of the representation.**—(1) The Authorised Officer shall take into account, representation, if any, made by the person or his legal nominee before the final determination of the price with respect to the forfeited property is made.

(2) The Authorised Officer shall thereafter fix the price of the forfeited property and intimate the same in writing to the person or his legal nominee.

6. **Issue of an Order selling the property to the Central Government.**—The State Government shall make an order to the effect that the forfeited property stands sold to the Central Government at the price fixed under rule 5 and send a copy of the said order to the concerned Ministry or Department of the Central Government, clearly indicating the name of the Treasury and Head of Account under which the amount so determined is to be deposited.

7. **Deposit of the amount by the Central Government.**—(1) The Central Government shall on receipt of the order under rule 6, deposit the price fixed for the forfeited property in such Treasury or under such Head of Account as may be specified therein under intimation to the person or his legal nominee.

(2) The amount of price along with interest thereon, shall be paid to the person or to his legal nominee.

[F. No. I-17014/52/2005-IS-VII]

L. C. GOYAL, Jt. Secy.